



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1050]
No. 1050]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 9, 2009/आषाढ़ 18, 1931
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2009/ASADHA 18, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2009

का.आ. 1678(अ).—जबकि दीमा हालम दाओगाह (जोएल) इसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित जिसे इसमें इसके बाद डीएचडी (जे) कहा गया है, का उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तरी कछार हिल्स जिले तथा इससे संटे असम के कार्बी आंगलांग, कछार और नागांव जिलों के दीमासा आबादी वाले क्षेत्रों और नागालैंड के दीमापुर जिले के हिस्सों को शामिल करके दीमासास के लिए एक अलग राज्य का निर्माण करना है;

और जबकि, डीएचडी (जे) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए :-

- (i) नागरिकों एवं सुरक्षा बलों के कर्मिकों की हत्या सहित हिंसा की गतिविधियों में संलिप्तता;
- (ii) फिरोती हेतु अपहरण के कार्यकलापों के अतिरिक्त, सरकारी विभागों के कर्मचारियों सहित सीधे-साधे नागरिकों को डराने-धमकाने, लूट-खसोट करने एवं उनके जीवन को खतरे में डालने जैसे कार्यकलापों में संलिप्तता;
- (iii) असम राज्य के महत्वपूर्ण ढांचागत एवं विकासक परियोजनाओं तथा उद्योगों के क्रियान्वयन में लगे कर्मचारियों पर हमला करना और धमकी देना;

- (iv) असम के उत्तरी कछार पर्वतीय जिले में रेलगाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमला करना तथा इसके द्वारा देश के संवेदनशील एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में महत्वपूर्ण संचार संयोजनों को विनष्ट करना;
- (v) क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर विपरीत निहितार्थों सहित असम के एनसी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में दिमासा एवं जेमी नागाओं के बीच जातीय हिंसा फैलाकर एवं संघर्ष कराकर समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना।

और जबकि, डीएचडी (जे) के विधिविरुद्ध एवं हिंसात्मक कार्यकलापों में ये शामिल हैं:-

- (i) वर्ष 2006, 2007, 2008 तथा 2009 में (15 मई, 2009 तक) हिंसा की क्रमशः 21, 63, 55 और 52 घटनाओं में शामिल होना
- (ii) वर्ष 2007, 2008, और 2009 (15 मई, 2009 तक) में क्रमशः 24 व्यक्तियों (7 सुरक्षा बल कर्मियों सहित), 63 व्यक्तियों (12 सुरक्षा बल कर्मियों सहित), 58 व्यक्तियों (13 सुरक्षा बल कर्मियों सहित) तथा 25 व्यक्तियों (13 सुरक्षा बल कर्मियों सहित) की हत्याएं करना

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह मानना है कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डीएचडी (जे) की उपर्युक्त गतिविधियां देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक तथा विघटनकारी हैं, सम्प्रदायों की बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली हैं तथा राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से खतरा है और कि यह एक विधिविरुद्ध संगम है;

अतः अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा डीएचडी (जे) को, इसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

और जबकि, यदि डीएचडी (जे) की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया गया अथवा नियंत्रित नहीं किया गया तो इसे निम्नलिखित के लिए अवसर मिलता रहेगा:-

- (i) अपनी विद्रोही एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने तथा तेज करने के लिए काँडरों की भर्ती करना तथा उन्हें सुदृढ़ बनाना;

- (ii) इस प्रयोजनार्थ अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों हेतु धन एकत्र करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर डराने-धमकाने और जबरन धन वसूली करने में संलिप्त रहना;
- (iii) विभिन्न स्रोतों तथा सीमा पार से और अधिक अवैध हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करना;
- (iv) अधिक से अधिक आम नागरिकों तथा सुरक्षा बल कर्मिकों की हत्याएं करना;
- (v) महत्वपूर्ण अवसंरचना, संचार साधनों तथा अन्य विकास परियोजनाओं के विरुद्ध हमले जारी रखना जिसके परिणामस्वरूप लोगों की सामान्य दिनचर्या में तथा महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों में बाधा उत्पन्न होती है; और
- (vi) सम्प्रदायों के बीच दुर्भाव तथा वैमनस्य को बढ़ावा देना तथा सौहार्द एवं शांति को गंभीर रूप से प्रभावित करना।

केन्द्र सरकार का यह भी राय है कि डीएचडी (जे) की उपर्युक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तथा पुलिस, सशस्त्र बलों और आम नागरिकों के खिलाफ डीएचडी (जे) द्वारा सतत रूप से तथा निरन्तर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए, डीएचडी (जे) को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है तथा तदनुसार, धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यक्षीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 11011/41/2008-एन.ई.-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9 July, 2009

S.O. 1678(E).—WHEREAS the Dima Halam Daogah (Joel) alongwith all its factions, wings and front organizations hereinafter referred to as DHD(J) have the aims and objectives of creation of a separate State for Dimasas comprising whole of North Cachar Hills district and adjoining Dimasa inhabited areas of Karbi Anglong, Cahar and Nagoan districts of Assam and parts of Dimapur district of Nagaland;

AND WHEREAS, the DHD(J) for fulfilling its objective has been:-

- (i) indulging in violent activities including killing of civilians and security force personnel;
- (ii) indulging in intimidation, extortion and endangering lives of innocent citizens including personnel of Government Departments, in addition to acts of kidnapping for ransom;
- (iii) attacking and threatening personnel engaged in the implementation of vital infrastructure and development projects, and industries in the State of Assam;
- (iv) attacking trains and railway stations in North Cachar Hills District of Assam thereby disrupting vital communications links in the sensitive and strategically important North Eastern Region of the country;
- (v) promoting enmity between communities and triggering ethnic violence and clashes among the Dimasas and Zemei Nagas in the North Cachar Hills district of Assam with serious adverse implications for the stability of the region.

AND WHEREAS, the unlawful and violent activities of DHD(J) include-

- (i) Involvement in 21, 63,55 and 52 violent incidents in 2006, 2007, 2008 and 2009 (upto 15th May 2009) respectively,

- (ii) killing of 24 persons (including 7 security forces), 63 persons (including 12 security forces), 58 persons (including 13 security forces) and 25 persons (including 13 security forces) in the years 2007, 2008 and 2009 (upto 15th May 2009) respectively,

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the aforementioned activities of DHD (J), for fulfilling its objectives are detrimental to and disruptive of, the territorial integrity of India, promote enmity between communities, and seriously threaten the security of the State, and that it is an unlawful association;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the DHD (J) alongwith all its factions, wings and front organizations to be as unlawful associations;

AND WHEREAS, if action to immediately curb and control the unlawful activities of the DHD (J) is not taken, it is likely to take the opportunity to-

- (i) continue to recruit and strengthen its cadres for expanding and escalating its subversive and violent activities;
- (ii) towards this end, continue to indulge in large scale intimidation and extortion with the aim of collecting funds for its unlawful activities;
- (iii) procure more illegal arms and ammunition from various sources and from across the borders;

- (iv) indulge in increased killings of civilians and security force personnel;
- (v) continue its attack against vital infrastructure, communications and other development projects leading to disruption of the normal life of people and vital supply lines; and
- (vi) promote disharmony and enmity among communities with serious implications for harmony and peace;

The Central Government is further of the opinion that having regard to the activities of DHD (J) mentioned above and to contain the sustained and ever increasing violence committed by DHD (J) against the police, the armed forces and the civilians, it is necessary to declare DHD (J) an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby, directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 11011/41/2008-NE. III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.